WITWAVES
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
Vol-2 Issue-3
(International Peer-Reviewed E-Journal)
(March 2025)

इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन के कानूनी पहलू

डॉ. आशीष पचौरी
संकायाध्यक्ष वाणिज्य
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

प्रस्तावना

आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन ने व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप बदल दिया है। इंटरनेट के माध्यम से वाणिज्यिक गतिविधियाँ, भुगतान प्रणाली, बैंकिंग और अन्य सेवाएँ अधिक सुलभ और तेज़ हो गई हैं। हालांकि, इसके साथ ही इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन से संबंधित कानूनी मुद्दे और सुरक्षा चिंता भी बढ़ गई हैं। इन डिजिटल ट्रांजेक्शनों में धोखाधड़ी, डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता और बौद्धिक संपदा जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन के कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करना है, जिसमें भारतीय कानून और अंतरराष्ट्रीय कानूनी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

कुंजीभूत शब्द –
इंटरनेट, डिजिटल ट्रांजेक्शन, वाणिज्यिक, साइबर अपराध, अधिनियम, क्रेडिट कार्ड।

इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन की परिभाषा

इंटरनेट ट्रांजेक्शन का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक लेन-देन, जैसे कि उत्पादों या सेवाओं का खरीदना, बेचना या किसी अन्य प्रकार की आर्थिक गतिविधि। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान, ई-वॉलेट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांजेक्शन शामिल हैं।

डिजिटल ट्रांजेक्शन को ऐसे लेन-देन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो डिजिटल माध्यमों (जैसे मोबाइल, कंप्यूटर या इंटरनेट) के माध्यम से संपन्न होते हैं। इसमें ऑनलाइन खरीदारी, बिल भुगतान, मनी ट्रांसफर और अन्य वित्तीय लेन-देन शामिल हैं।

भारतीय कानूनी ढांचा

भारत में इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन के कानूनी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए कई कानून और नीतियाँ मौजूद हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कानून और उनकी धारा इस प्रकार हैं:

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) भारतीय इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े मामलों को मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत नियंत्रित किया जाता है। यह अधिनियम इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, साइबर अपराध और डिजिटल दस्तावेजों की वैधता को सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, डेटा चोरी और साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान हैं। धारा 66C और 66D धाराएँ इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करती हैं। इन धाराओं के तहत साइबर अपराधियों को दंडित किया जाता है जो धोखाधड़ी के तहत व्यक्तिगत जानकारी चुराते हैं या फर्जी लेन-देन करते हैं।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (Information Technology (Amendment) Act, 2008) इस अधिनियम के तहत, इंटरनेट पर होने वाली धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को कड़े तरीके से नियंत्रित किया गया है। यह अधिनियम ईमेल और अन्य ऑनलाइन संचार के माध्यम से हो रही अपमानजनक गतिविधियों को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान प्रदान करता है।

3. डिजिटल भुगतान और सुरक्षा के लिए नियम (Payment and Settlement Systems Act, 2007) इस कानून के तहत, भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली की सुरक्षा और निगरानी की जाती है। यह अधिनियम राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और अन्य वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करता है जो डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करते हैं।

4. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019) इस बिल के तहत, इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन के दौरान व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े

प्रावधान हैं। यह कानून डेटा की संग्रहण, उपयोग, प्रसंस्करण और उसे सुरक्षित रखने के लिए कंपनियों को दिशानिर्देश प्रदान करता है।

डिजिटल ट्रांजेक्शन के कानूनी मुद्दे

1. **धोखाधड़ी और साइबर अपराध:** इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन में सबसे बड़ी चिंता धोखाधड़ी और साइबर अपराध की है। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, डेटा चोरी और फिशिंग हमले जैसी समस्याएँ आम हैं। इससे उपभोक्ताओं का वित्तीय नुकसान हो सकता है और उनकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है। भारत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां धोखाधड़ी के जरिए ऑनलाइन लेन-देन के द्वारा उपभोक्ताओं के बैंक खातों से पैसे निकाल लिए गए।

2. **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** डिजिटल ट्रांजेक्शन के दौरान उपभोक्ताओं का व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा साझा किया जाता है। इसलिए डेटा गोपनीयता और सुरक्षा का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। डेटा की चोरी और अवैध प्रसंस्करण से बचाव के लिए उपभोक्ताओं को सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न हैकिंग घटनाएँ हुई हैं, जिनमें उपयोगकर्ता डेटा चुराए गए हैं।

3. **उपभोक्ता संरक्षण:** ऑनलाइन लेन-देन के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि उन्हें धोखाधड़ी से बचाया जा सके। इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपभोक्ताओं को रिफंड और रिटर्न नीतियों के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए।

4. **संविदात्मक और अनुबंध संबंधी विवाद:** इंटरनेट के माध्यम से लेन-देन के दौरान कई बार अनुबंधों और समझौतों के उल्लंघन के मामले सामने आते हैं। इस तरह के मामलों में कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यदि कोई ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी करता है

और उत्पाद की गुणवत्ता या सर्विस से संतुष्ट नहीं होता, तो वह कानूनी प्रक्रिया का सामना कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय कानूनी पहलू

इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई कानूनी प्रावधान और समझौतें हैं।

1. **यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा सुरक्षा विनियमन (GDPR):** यूरोपीय संघ में लागू GDPR इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन के दौरान व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह कानून कंपनियों को उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कड़े दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

2. **अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी पर कन्वेंशन (Budapest Convention on Cybercrime):** यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है।

सुरक्षा उपाय और समाधान

1. **सुरक्षित भुगतान गेटवे और एन्क्रिप्शन:** ऑनलाइन लेन-देन के दौरान डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और सुरक्षित भुगतान गेटवे जैसे उपायों का पालन करना चाहिए।
2. **दो-चरणीय प्रमाणीकरण:** उपभोक्ताओं और व्यापारियों को दो-चरणीय प्रमाणीकरण (2FA) जैसे सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए, ताकि ट्रांजेक्शन अधिक सुरक्षित हो।
3. **सतर्कता और उपभोक्ता शिक्षा:** उपभोक्ताओं को डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए नियमित रूप से सतर्क किया जाना चाहिए। इसके लिए जागरूकता अभियान और शिक्षा की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन आज के वाणिज्यिक क्षेत्र का अहम हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि, इसके साथ ही कानूनी और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचों का पालन करना, डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के उपायों को बढ़ावा देना इन ट्रांजेक्शनों के सुरक्षित संचालन के लिए महत्वपूर्ण है।

संदर्भ सूची

1. Information Technology Act, 2000, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India.
2. Personal Data Protection Bill, 2019, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India.
3. Payment and Settlement Systems Act, 2007, Reserve Bank of India.
4. General Data Protection Regulation (GDPR), European Union.
5. Cybercrime and Internet Fraud, Cyber security Journal, 2021.
6. Budapest Convention on Cybercrime, Council of Europe, 2001.
7. Digital Transactions and Legal Issues, Journal of Internet Law, 2022